और जो मैंने सुझाव दिये हैं, उन पत्रिकाओं और अखबारों को पाबन्दी लगाइये जिनमें इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा छापा जाता है, कहानियां बनाई जाती हैं जिससे लोग क्राइम करना सीखते है। क्या सरकार इन क्राइम्स को रोकने के लिये इस तरह के सुझाव पर विचार करने जा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। एक तो यह है कि ऐसी पत्रिकाएं जो इस प्रकार के क्राइम्स की मनोवृत्ति को बढ़ाने को प्रोत्साहित करती हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है और मैं इस बारे में इंफार्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टरी के साथ चर्चा करूंगा। जहां तक कारतूस पर निशान लगाने का सवाल है, यह अच्छा सुझाव है चाहे इम्पोर्ट किया हुआ कारतूस हो या भारत में बना हुआ हो, उन पर निशान रहेगा तो यह बात सही है कि यह पता लगाया जा सकता है कि यह कारतूस किस लाइसेंसहोल्डर को मिला है और अगर कारतूस उसके पास नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

जहां तक क्रिमिनल प्रोसीजर को अमैंड करने का सवाल है, वह सारा विचाराधीन है लेकिन इस बीच क्राइम को और इन्वैस्टीगेशन को अलग करने पर गृह-मन्त्रालय में अलग से विचार चल रहा है ताकि क्राइम का इन्वैस्टीगेशन दूसरा करे और क्राइम रजिस्टर दूसरी ब्रांच करे। इस बात की हिदायत पुलिस को दी गई है कि एफ० आई० आर० रजिस्टर करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न करे और जितनी भी शिकायत आयें उन सब की एफ० आई० आर० तुरन्त दर्ज की जाये।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : दोनों को अलग-अलग करेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अभी तो मैंने कहा है।

13.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty-five minutes past Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled, after lunch, at forty two minutes past Fourteen of the Clock.

14.42 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY SPEAKER : Now matters under Rule 377. Shrimati Madhuri Singh.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for providing requisite facilities in Purnea (Bihar) which has been declared industrially backward area.

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समस्या की ओर आप का ध्यान दिलवाना चाहती हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिया (बिहार) गत 6 माह से औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किया गया है, परन्तु जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र को मिलनी चाहिए वह अभी तक इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो रही हैं जिसके कारण क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं।

साथ ही विद्युत समस्या भी इस क्षेत्र में बहुत है। इसके समाधान हेतु यहां पर (पूर्णिया) विद्युत घर बनाने हेतु सर्वे हुआ, वह कार्य भी विगत एक वर्ष से लम्बित है।

मैं केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अनुरोध करती हूं कि इस समस्या को बिहार सरकार द्वारा हल करवाने का प्रयास किया जाय जिससे लाखों नागरिकों को लाभ मिल सके।

(ii) Non-payment of sugarcane arrears by Mahalaxmi Sugar Mills, Iqbalpur (U. P.) and need to take it over.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत "दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स इकबालपुर (जनपद सहारनपुर, उ० प्र०)" के कई वर्षों से बीमार चलते रहने की ओर सरकार एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कई बार करा चुका हूं और इस मिल का अधिग्रहण करने हेतु अनुरोध भी कर चुका हूं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ पुनः कहना पड़ रहा है कि इस संदर्भ में आज तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया। परिणामस्वरूप गन्ना किसानों का करीब ढ़ाई करोड़ रुपया गत वर्ष एवं चालू पेराई वर्ष में इस